भारत, झींगा, जबरन श्रम

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में खेतों में पाले जाने वाले झींगे के उत्पादन में वयस्कों के जबरन श्रम का उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में केंद्रित झींगा छीलने के शेड और प्रसंस्करण संयंत्रों में, पाले जाने वाले झींगा के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए आंतरिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी पर रखा जाता है, जो सामान्यतः हाशिए पर रहने वाली सामाजिक जातियों से होते हैं। छीलने के शेड में, जहां काम करने की सबसे खराब स्थिति की सूचना मिलती है, अधिकतर महिलाएँ काम पर रखी जाती हैं । तीसरे पक्ष के श्रम ठेकेदार हाशिए पर पड़े समुदायों से श्रमिकों की भर्ती करते हैं और नौकरी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा शुल्क लेते हैं। भुगतान करने में असमर्थ, जो कि कभी-कभी पूरे महीने की मजदूरी के बराबर हो सकता है, कई श्रमिक अक्सर श्रम ठेकेदार से ऋण लेते हैं, और पूरा ऋण चुकाए जाने तक, नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऋण बंधन होता है। श्रमिक अक्सर कार्यस्थल पर या उसके आस-पास नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हैं—जो आमतौर पर किसी दूरस्थ स्थान पर होता है—और ताला लगाने और निगरानी सहित सख्त सुरक्षा उपाय, श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से परिसर से बाहर निकलने से रोकते हैं। यह स्थिति भोजन, आश्रय, व्यक्तिगत स्वच्छता और बाज़ार के सामान तक पहुँच जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियोक्ता पर कई निर्भरताएँ पैदा करती है। झींगा को प्रसंस्करण के काम में रसायनों के संपर्क में आना, अत्यधिक ठंड, लंबे समय तक खड़े रहना और चोट लगने का उच्च जोखिम शामिल हैं, जो कभी-कभी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बिना किया जाता है। यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार सहित मौखिक और शारीरिक शोषण, कथित तौर पर प्रचलित हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आवास सुविधाएं सामान्यतः भीड़भाड़ वाली, गंदी और खराब रखरखाव वाली होती हैं। कानूनी सीमाओं से परे अत्यधिक ओवरटाइम की रिपोर्टें हैं, प्रायः बिना वेतन के। आंतरिक प्रवासी श्रमिक—जो सामान्यतः अपने परिवारों और घरों से दूर होते हैं और जिनके पास झींगा प्रसंस्करण के अतिरिक्त नौकरी के बहुत कम या कोई अवसर नहीं होते हैं—अक्सर श्रम ठेकेदारों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षाकर्मियों द्वारा धमकाये जाने और नौकरी से निकाले जाने की धमकियों का सामना करते हैं, यदि वे प्रतिबंधात्मक और शोषणकारी श्रम नीतियों का पालन करने में विफल रहते हैं । श्रमिकों को कानूनी रूप से आवश्यक न्यूनतम वेतन नहीं मिलने और 2 वर्ष तक अपना वेतन प्राप्त किए बिना काम करने की रिपोर्टें मिली हैं। श्रमिकों द्वारा महीनों तक बहुत कम या बिना छुट्टी के काम करने की कई रिपोर्टें मिली हैं।